

हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने बहिर, हरियाणा और सक्किम के [ग्रामीण स्थानीय निकायों](#) के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें [वित्त आयोग](#) (XV FC) अनुदान वितरित किया है।

मुख्य बिंदु

- अनुदान का आवंटन:
 - हरियाणा:
 - हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202.47 करोड़ रुपए की अनटाइड अनुदान की दूसरी कसित प्राप्त हुई।
 - यह धनराशि 18 पात्र ज़िला पंचायतों, 142 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,195 पात्र ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित की गई है।
 - बहिर:
 - बहिर को 821.80 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी कसित प्राप्त हुई।
 - ये धनराशि 38 ज़िला पंचायतों, 530 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 8,052 पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई है, जिन्होंने रलीज के लिये अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं।
 - सक्किम:
 - सक्किम को 6.26 करोड़ रुपए की कुल संयुक्त अनुदान की दूसरी कसित प्राप्त हुई।
 - ये धनराशि 4 पात्र ज़िला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई, जिन्होंने जारी करने के लिये अनिवार्य शर्तें पूरी कीं।
 - अनटाइड एवं टाइड अनुदानों का उपयोग:
 - अप्रतिबंधित अनुदान:
 - पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग [संवधान की ग्यारहवीं अनुसूची](#) में सूचीबद्ध 29 वषियों के अंतर्गत स्थान-वशिष्ट आवश्यकताओं के लिये कर सकते हैं।
 - इन अनुदानों का उपयोग वेतन और स्थापना लागतों के लिये नहीं किया जा सकता।
 - बंधे हुए अनुदान:
 - इन नधियों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये, जिनमें शामिल हैं:
 - स्वच्छता और [खुले में शौच से मुक्त \(ODF\) स्थिति का रखरखाव](#), जसमें [अपशिष्ट प्रबंधन](#) और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
 - पेयजल आपूर्ति, [वर्षा जल संचयन](#) और [जल पुनर्चक्रण](#)।

वित्त आयोग

- यह एक [संवैधानिक निकाय](#) है, जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर आय के वितरण की वधि और नियम निर्धारित करता है।
- संवधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को पाँच वर्ष के अंतराल पर या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- प्रथम [वित्त आयोग](#) की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और अब तक पंद्रह वित्त आयोग स्थापित हो चुके हैं।

15वाँ वित्त आयोग

- एन.के. सहि की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को योजना आयोग की समाप्ति और [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#) लागू होने की पृष्ठभूमि में किया गया था।
- नवंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [15वें वित्त आयोग](#) को पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिये इसके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/grants-for-rural-local-bodies-of-haryana>

